

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग—२
संख्या: /XVIII(II)/2014-20(01)/2014
देहरादून: दिनांक: २५ जून, 2014

कार्यालय ज्ञाप

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा नया भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रख्यापित किया गया है।

2— अतः उक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—12 में अन्तर्निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक सर्वेक्षण व सर्वेक्षण के लिए निम्नानुसार सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

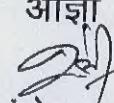
1. सम्बन्धित नायब तहसीलदार।
2. अर्जन/अपेक्षक निकाय के तहसील स्तर के अधिकारी (अनुपलब्धता की दशा में जिला या राज्य स्तर के अधिकारी)।
3. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या—४३७(१) /XVIII(II)/2014 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बंडोनी)
उप सचिव।